गोवा नमूना कर्मचारी संघ

बनाम

जनरल सुपरइंटेन्डेंस कंपनी ऑफ भारत प्राईवेट लिमिटेड और अन्य

11 दिसंबर, 1984

[डी. ए. देसाई और अमरेंद्र नाथ सेन, जे. जे.]

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, धारा 2 (ए) (1) और 10 (1) (डी)।

केंद्र शासित प्रदेश में औद्योगिक विवाद-क्या केंद्र सरकार विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेजने के लिए निजी सरकार को मंजूरी देती है।

भारत का संविधान 1950, अनुच्छेद 239,

केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन '-प्रशासक-केंद्र सरकार क्या किसी केंद्र शासित प्रदेश में औद्योगिक विवाद को संदर्भित करने के लिए' उपयुक्त सरकार 'है

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत औद्योगिक न्यायाधिकरण को।

सामान्य खंड अधिनियम 1897 धारा 3 (8), 3 (60), 3 एक्स (62 ए)।

'केंद्र सरकार '-' राज्य सरकार '-केंद्र शासित प्रदेश'-'प्रशासन'

केंद्र शासित प्रदेश का विभाजन '-' के बीच का अंतर।

शब्द और वाक्यांश-इसका अर्थः

'उपयुक्त सरकार '-धारा 2 (ए) (1) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संबंध में-धारा 3 (8) (बी) (iii) और 3 (60) (ग) सामान्य खंड अधिनियम 1897

केंद्र सरकार ने एक 'उपयुक्त सरकार' के रूप में संदर्भित किया कि अपीलार्थी-कर्मचारी संघ और कर्मचारी संघ के बीच औद्योगिक विवाद प्रथम प्रत्यर्थी-धारा के तहत प्रत्येक अपील में नियोक्ता। 10 (1) (घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 से केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण तक।

एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि केंद्र सरकार उक्त औद्योगिक विवादों के संबंध में 'उपयुक्त सरकार' नहीं थी और इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के पास अधिनियम की धारा 10 (1) (घ) के तहत कोई शक्ति नहीं है में पाँच संदर्भ दिए गए है और यह कि न्यायाधिकरण के पास उस पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। अपीलकर्ता संघ ने इस आपत्ति को यह तर्क देते हुए खारिज कर दिया कि कर्मचारी काम करने वाले श्रमिक (रोजगार विनियमन) अधिनियम, 1948 में अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर 'डॉक श्रमिक' थे और चूंकि वे केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव के एक प्रमुख बंदरगाह मोरमुगाओ बंदरगाह में काम कर रहे थे, इसलिए केंद्र सरकार औद्योगिक विवाद के संबंध में 'उपयुक्त सरकार' होगी और इसके परिणामस्वरूप वैध और सक्षम थे।

न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि संदर्भ द्वारा अंतर्गत आने वाले लौह अयस्क के नमूने लेने वाले कर्मचारी 'डॉक श्रमिक' थे। जैसा कि डॉक श्रमिक को (रोजगार विनियमन) अधिनियम, 1948 में परिभाषित किया और जैसा कि वे एक प्रमुख क्षेत्र में काम कर रहे थे। बंदरगाह, एक केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र सरकार 'उपयुक्त' सरकार होगी। न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि प्रारंभिक आपत्ति और अंतिम सुनवाई के लिए संदर्भ निर्धारित करें।

प्रथम उत्तरदाता-नियोक्ताओं ने अनुच्छेद 227 के तहत आवेदन दायर किए। उच्च न्यायालय ने कहा कि श्रमिक, जो लौह अयस्क के नमूने लेने वाले थे, न ही डॉक

में परिभाषित 'डॉक श्रमिकों' अभिव्यक्ति में समझा गया श्रमिक (रोजगार विनियमन) अधिनियम, 1948 और न ही किसी कार्य में शामिल किसी प्रमुख बंदरगाह से जुड़ा हुआ या उससे संबंधित किसी भी केन्द्र में शामिल नहीं थे। एक प्रमुख बंदरगाह से संबंधित परीक्षण विवाद और इसलिए केंद्र सरकार औद्योगिक विवाद को संदर्भित करने के लिए उपयुक्त सरकार नहीं थी इसके आगे कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार नहीं है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (ए) (आई) के तहत केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव, लेकिन यह अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक है और इसलिए केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार नहीं है और उसे संदर्भ देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। नियम को पूर्ण बना दिया गया और संदर्भों को रद्द कर दिया गया।

न्यायालय ने अपीलों की अनुमति देते हुए अभिनिर्धारित किया

1. केंद्र सरकार 'उपयुक्त सरकार' के रूप में संदर्भ दिया था। उच्च न्यायालय ने संदर्भों को रद्द करने में स्पष्ट रूप से गलती की थी। उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1) के तहत केंद्र सरकार की क्षमता के बारे में प्रारंभिक बिंदु पर न्यायाधिकरण के फैसले की पुष्टि की जाती है। न्यायाधिकरण इस तर्क की जांच करने के लिए स्वतंत्र होगा कि क्या लौह अयस्क के नमूने लेने वाले किसी प्रमुख बंदरगाह से जुड़े या उससे संबंधित किसी भी काम में शामिल हैं या वे गोदी कर्मचारी हैं और उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से प्रभावित हुए बिना अपने स्वयं के निर्णय पर आते हैं। चूंकि विवाद पुराना है, इसलिए न्यायाधिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है और छह महीने की अवधि के भीतर मामले का निपटारा करना है। [386 जी; 387 डी-ई, सी]

2 (i) निर्विवाद रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 एक केंद्रीय अधिनियम है जो सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के प्रारंभ के बाद लागू होता है और प्रासंगिक परिभाषाओं को संवैधानिक और वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुनर्गठित किया गया है। 'केंद्र सरकार', 'राज्य सरकार' और 'केंद्र शासित प्रदेश' अभिव्यक्तियों को सामान्य खंड अधिनियम, 1897 में प्रत्येक को सौंपा गया अर्थ प्राप्त होना चाहिए, जब तक कि उस विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो, जिसमें इसका उपयोग किया जाता है उसमें कुछ भी प्रतिकूल न हो। इस तरह की प्रतिकूलता को न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाई गई। [384 बी-सी]

(ii) संविधान के सुसंगत प्रावधानों के संबंध में और केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार की अवधारणा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए विदेशी है और अनुच्छेद 239 में प्रावधान है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना है। राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य कर सकता है। प्रशासक इस प्रकार वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है। उनकी स्थिति उससे बिल्कुल अलग है। किसी राज्य के राज्यपाल का, प्रशासक अपने मंत्री के साथ मतभेद कर सकता है और फिर उसे राष्ट्रपति के आदेश प्राप्त करने होंगे, जिसका अर्थ है केंद्र सरकार का आदेश प्राप्त करना होगा। इसलिए केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राज्य सरकार के विवरण के लिए योग्य नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार 'उपयुक्त सरकार' है। [384 एफ-जी)

(iii) उच्च न्यायालय के खंड (ग) की व्याख्या करने में त्रुटि हुई। सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 (60) जो अपने सही अर्थ पर यह दर्शाती है कि केंद्र शासित प्रदेश में राज्य सरकार की कोई अवधारणा नहीं है, लेकिन जहां भी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में 'राज्य सरकार' अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है, केंद्र सरकार

राज्य होगी। इस संदर्भ में केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में राज्य सरकार की अवधारणा को परिभाषा द्वारा खत्म कर दिया गया है। [383 डी-एच]

सत्य देव बुशहरी बनाम पदम देव और अन्य [1955] एससीआर 549 और द मध्य प्रदेश राज्य बनाम श्री मौला बक्स और अन्य। [1962] 2 एससीआर 794, अनुपयुक्त ठहराया गया।

3.(i) तीन अभिव्यक्तियों 'केंद्र सरकार' की परिभाषा (धारा 3) सामान्य खंड अधिनियम, 1897 में स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा कि संविधान और संसद ने भी इन परिभाषाओं को लागू करने में स्पष्ट रूप से राज्य सरकार और संघ के प्रशासन के बीच अंतर बनाए रखा संविधान द्वारा प्रदत्त क्षेत्र। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया जाता है प्रशासन के संबंध में 'केंद्रीय सरकार' अभिव्यक्ति की परिभाषा केंद्र शासित प्रदेश का गठन, जिसके दायरे में कार्य करने वाला उसका प्रशासक संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत उन्हें दिया गया अधिकार। होगा। 'केंद्र सरकार' अभिव्यक्ति में समझा गया। जब यह समावेशक भाग की परिभाषा में बहिष्करण भाग के साथ संयोजन में रखा गया है अभिव्यक्ति 'राज्य सरकार' जो यह प्रावधान करती है कि किसी भी कार्य के संबंध में या संविधान के प्रारंभ के बाद किया जाना (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 का अर्थ होगा, किसी राज्य में राज्यपाल और किसी केंद्र शासित प्रदेश में - केंद्र सरकार, अभिव्यक्तियों के बीच वैचारिक रूप से अंतर राज्य सरकार 'और' केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन स्पष्ट रूप से उभरता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभिव्यक्ति, एक का प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश ', प्रशासक जिस तरह से वर्णित किया गया है, नहीं होगा 'राज्य सरकार' वाक्यांश में समझा गया जैसा कि किसी भी अधिनियम में उपयोग किया जाता है इन परिभाषाओं को उनके वर्तमान रूप में लाने के लिए संशोधित किया गया है विधियों का अनुकूलन (संख्या 1) आदेश, 1956। [386 ई-जी]

(ii) उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से एक त्रुटि में पड़ गया जब उसने कहा कि राज्य सरकार अभिव्यक्ति की समावेशी परिभाषा, आवश्यक नहीं है अभिव्यक्ति के दायरे को बढ़ाएँ लेकिन कभी-कभी इसके विपरीत की ओर इशारा कर सकते हैं। [386 सी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील स. 4904- 4908/1984

बॉम्बे उच्च न्यायालय के विशेष सिविल आवेदन सं. 97 बी/80,98 बी/80, 100 बी/80,99 बी/80 और 67 बी/80 में निर्णय और आदेश 19.9.83 दिनांक से

वी. ए. बोबडे, के. जे. जॉन और सुश्री एन. श्रीवास्तव लांट- अपीलकर्ता।

एफ. एस. नरीमन, सुश्री ए. सुभाषिनी, एम. एस. उसगाओकर, एस. के. मेहता- उत्तरदाता पी. एन. पुरी और एम. के. दुआ।

न्यायालय का निर्णय देसाई, जे. द्वारा सुनाया गया।

विशेष अवकाश दिया गया।

फिर से एक पूरी तरह से अस्थिर प्रारंभिक आपत्ति की कठोरता और एक दशक का मूल्यवान समय इस विचित्र अभ्यास में बर्बाद हो जाता है, जो सामाजिक-आर्थिक न्याय की खोज को निराश करता है, जिससे यह एक ऑप्टिकल भ्रम नहीं तो इसका सपना बन जाता है।

एक उपयुक्त सरकार के रूप में केंद्र सरकार अपीलार्थी-गोवा सैंपलिंग के बीच औद्योगिक विवाद को संदर्भित किया गया कर्मचारी संघ (संक्षेप में 'संघ') और पहला धारा के तहत प्रत्येक याचिका में प्रतिवादी (संक्षेप में 'नियोक्ता')। 10 (1) (घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में 'अधिनियम') कर्मचारियों को भेजना सभी संदर्भों में आम है, नियोक्ता अलग है किराया लेकिन प्रत्येक एक आम सवाल उठाता है। जब संदर्भ सुनवाई के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष आया, ऐसा प्रतीत होता

है कि वे प्रत्येक मामले में षड्यंत्रकारी ने प्रारंभिक आपत्ति जताई लेकिन क्या था किसी प्राधिकरण के लिए कुछ अपील जो अभिलेख में स्पष्ट नहीं की गई है ऐसा प्रतीत होता है कि मामले न्यायाधिकरण को प्रेषित किए गए थे और वहाँ सभी पाँच संदर्भों के बाद केंद्रीय को स्थानांतरित कर दिया गया सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 1 (संक्षेप में "न्यायाधिकरण") को स्थानांतरित कर दिए गए।

जब न्यायाधिकरण के समक्ष फिर से संदर्भ सामने आए सुना, इतिहास दोहराया। एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि संघ के बीच औद्योगिक विवाद के संबंध में केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार नहीं थी और नियोक्ता और इसलिए, केंद्र सरकार के पास धारा के तहत कोई शक्ति नहीं थी। 10 (1) (घ) अधिनियम का निर्देश देने के लिए और तदनुसार न्यायाधिकरण के पास इस पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। संघ ने इस तर्क को यह आग्रह करते हुए पलटने का प्रयास किया कि कर्मचारी डॉक श्रमिक (रोजगार विनियमन) अधिनियम, 1948 में अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर डॉक श्रमिक थे और चूंकि वे एक प्रमुख बंदरगाह में काम कर रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार संघ और श्रमिकों के बीच औद्योगिक विवाद के संबंध में उपयुक्त सरकार होगी और इसलिए, संदर्भ वैध है और न्यायाधिकरण को कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर इससे निपटना चाहिए। धनुष की दूसरी डोर के रूप में, यह तर्क दिया गया था कि केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार है

ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण के समक्ष दोनो पक्षों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे। न्यायाधिकरण साक्ष्यों की पूरी तरह से जांच करने के बाद माना कि संदर्भ में शामिल किए गए कर्मचारी कॉम होंगे अभिव्यक्ति 'डॉक श्रमिकों' की परिभाषा में डी के रूप में प्रस्तुत किया गया गोदी कर्मचारी (रोजगार विनियमन) अधिनियम में जुर्माना और क्योंकि वे मोरमुगाओ बंदरगाह पर काम कर रहे थे जो एक प्रमुख बंदरगाह है, उनके द्वारा उठाए गए औद्योगिक विवाद के संबंध में केंद्रीय सरकार उपयुक्त

सरकार होगी। इसके ट्रिब्यूनल ने जांच करने के लिए आगे बढ़े कि क्या संदर्भ होगा इस धारणा पर सक्षम कि कर्मचारी शामिल नहीं हैं कर्मचारियों द्वारा गठित एक प्रमुख बंदरगाह में है और विवाद उत्पन्न होता है प्रमुख बंदरगाह में किए गए कर्तव्य और कार्य से बाहर सरकार आवश्यक संदर्भ बनाए। तब न्यायाधिकरण ने वैकल्पिक प्रस्तुति पर विचार करने के लिए आगे बढ़े कि क्या संदर्भ सक्षम होगा, भले ही राज्य सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गोवा, दमन और दीव पहले में निर्धारित केंद्र शासित प्रदेश का गठन करता है संविधान और उसके प्रशासन की अनुसूची का पालन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद के अधीन नियुक्त प्रशासक द्वारा चलाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 239 में केंद्र सरकार भी उपयुक्त सरकार है। प्रतिद्वंद्वी विवादों पर चर्चा करने के बाद न्यायाधिकरण ने इस विवाद पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया। न्यायाधिकरण ने प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया और 14 जुलाई, 1980 के अपने आदेश द्वारा अंतिम सुनवाई के लिए निर्धारित कर दिया।

प्रत्येक संदर्भ में नियोक्ता ने कला के तहत विशेष नागरिक आवेदन दायर किया। न्यायपालिका के उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 227 बॉम्बे में। सभी पाँच विशेष दीवानी आवेदन अंतिम सुनवाई के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय की पणजी पीठ के समक्ष आए और उन्हें एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया गया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि लौह अयस्क के नमूने, कर्मचारी अपीलार्थी द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि है। संघ किसी प्रमुख बंदरगाह से जुड़े या उससे संबंधित किसी भी कार्य में शामिल नहीं हैं। आगे उच्च न्यायालय ने कहा कि जिस औद्योगिक विवाद में लौह अयस्क के नमूने लेने वाले शामिल हैं, वह बंदरगाह से संबंधित औद्योगिक विवाद नहीं है। आैद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(क)(i) और न ही श्रमिकों को 'पूर्व श्रमिकों में डॉक' के अभिव्यक्ति में शामिल किया गया है। जैसा कि डॉक श्रमिकों (रोजगार विनियमन) में परिभाषित किया गया है। अधिनियम, 1948 और इसलिए, केंद्र

सरकार औद्योगिक विवाद को प्राधिकरण में भेजने संदर्भित के लिए उपयुक्त सरकार नहीं है। इस दलील के दूसरे पहलू पर विचार करते हुए कि केंद्र सरकार को ही केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के लिए राज्य सरकार कहा जा सकत है। गोवा उच्च न्यायालय ने माना कि केंद्रीय सरकार राज्य के लिए केन्द्र सरकार नहीं है। अधिनियम के 2 (क) (ii) का लेकिन यह प्रशासक है भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त, जो केंद्र शासित प्रदेश गोवा और दीव के लिए राज्य सरकार है और वह धारा के अर्थ में उपयुक्त सरकार है। अधिनियम के 2(क) उच्च न्यायालय यदि महसूस करता है कि केंद्रीय सरकार को राज्य सरकार भी माना जाता है तो केंद्र शासित प्रदेश गोव, दमन और दीव के लिए दो राज्य सरकारे होगी और इससे पूरी तरह से भ्रम पैदा होगा। तदनुसार उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रशासक इसके लिए उपयुक्त सरकार है। अधिनियम के 2(क)(i) अधिनियम और इसलिए केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार नहीं थी और उसके पास विवादित संदर्भ देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इस निष्कर्ष के अनुसार, उच्च न्यायालय ने संदर्भों को रद्द करते हुए नियत को पूर्ण बना दिया। अतः विशेष अनुमति द्वारा यह अपील की। जिस प्रश्न पर हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए वह यह है कि क्या संघ और उपयुक्त नियोक्ता द्वारा भेजे गए कर्मचारियों के प्रतिनिधि के बीच औद्योगिक विवाद से संबंधित है। जो उचित सरकार है जो अधिनियम की धारा 10 के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकती है। अधिनियम की धारा 10 यह प्रावधान करती है कि जहां उपयुक्त सरकार को आशंका होने पर वह किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा विवाद आदि को न्याय-निर्णय के लिए न्यायाधीकरण को भेज सकती है। इस अनुभाग में दो प्रावधान है जो वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रारंभिक नहीं है। किसी आैद्योगिक विवाद के न्याय-निर्णय के लिए संदर्भ देने की शक्ति प्रदान की जाती है जो या तो मौजूद है या संदिग्ध है।

'उपयुक्त सरकार' को अधिनियम की धारा 2 (ए) में परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 2 (ए) का अर्थ है '(i) संबंधित किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा या उसके अधीन चलाया जाने वाला कोई भी उद्योग सरकार (वर्तमान के लिए प्रासंगिक नहीं शब्दों को छोड़कर), एक प्रमुख बंदरगाह, केंद्र सरकार, और (ii) किसी भी अन्य औद्योगिक विवाद के लिए, राज्य सरकार।

नियोक्ता में तर्क दिया कि प्रत्येक मामले में संघ द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए कर्मचारी लौह अयस्क के नमूने लेने वाले है और वे किसी प्रमुख बंदरगाह के काम से जुड़े नहीं है और किसी भी प्रमुख बंदरगाह के काम से जूड़े नहीं है या उनके काम में और इसलिए धारा 2 (क) (i) आकर्षित नहीं होगी। निष्कर्ष के रूप में यह प्रस्तुत किया गया था कि मामला अवशिष्ट खंड में आएगा (ii) और इसलिए, राज्य सरकार उपयुक्त होगी। कर्मचारियों ने यह कहकर विवाद को खारिज कर दिया कि वे प्रमुख बंदरगाह में काम करने वाले कर्मचारी हैं मुकदमे का विवाद सीधे तौर पर कार्यप्रणाली और प्रशासन को छूता है। इसलिए, केंद्र सरकार है उपयुक्त सरकार। वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया गया था कि यहाँ संघ/अपीलार्थी की ओर से उस संबंध में कोई भी दर एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए, कोई राज्य सरकार और केंद्रीय नहीं है सरकार, अगर इसे एक ही कहा जा सकता है, तो एकमात्र सरकार है राज्य सरकार के अभाव में केंद्रीय सरकार के पास राज्य सरकार के सभी अधिकार भी होंगे और इसलिए, केंद्र सरकार उपयुक्त होगी।

यह दूसरे प्रकार का अंग है और इस विवाद का उत्तर देकर अपीलों का अंतिम निपटारा किया जा सकता है। क्योंकि हमारी इन समझौतों का जवाब देकर अपीलों का अंत में दूसरे पहलू की हम गुण-दोष पर विवाद से निपटने से पहले, यह आवश्यक है विवाद से संबंधित संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

अनुच्छेद 239 (1) यह प्रावधान करता है कि 'अन्यथा प्रदान किए गए कानून को छोडकर, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति द्वारा उस सीमा तक जब कि वह अपने द्वारा निर्दिष्ट पदनाम से प्रशासित किया जायेगा। 'अनुच्छेद 239ए जिसे संविधान के (चौदहवाँ संशोधन) अधिनियम द्वारा जोड़ा गयाा। 1962 संसद को शक्ति प्रदान करता है कानून द्वारा स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण करना गोवा, दमन और दीव सहित कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए।वह कानून जिसके द्वारा स्थानीय विधानमंडल और/या मंत्रिपरिषद बनाई है। जा प्रत्येक मामले में उनके संविधान, शक्तियों और कार्यों को निर्दिष्ट करेंगे उपअनुच्छेद (2) यह सुनिश्चित किया गया था कि ऐसा कानून जब अधिनियमित किया जाता है तो इसका संशोधन नहीं माना जाएगा अनुच्छेद के उद्देश्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 240 को राष्ट्रपति उसमें निर्दिष्ट केन्द्रशासित प्रदेश की शांति प्रगति अच्छी सरकार के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। अनुच्छेद 246 (4) में प्रावधान है कि संसद को भारत के किसी भी हिस्से के लिए जो राज्य में शामिल नहीं है, किसी भी मामले में कानून बनाने की शक्ति है भले ही एेसा मामला राज्य सूची में शामिल हो। अभिव्यक्ति 'केंद्र सरकार' है को परिभाषित किया गया है। सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3(8) (वर्तमान उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक शब्दों को हटाकर) निम्नानुसार हैंः

"(8) "केंद्र सरकार"

(अ)

(ख) संविधान के प्रारंभ के बाद किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में संविधान के प्रारंभ राष्ट्रपति से अभिप्रेत है और शामिल होगा।

(i)

(ख)

(ग) किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संबंध में, उसका प्रशासक संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत उसे दिये गए अधिकार के दायरे में कार्य कर रहा है।

'राज्य सरकार' शब्द को धारा 33(60) में परिभाषित किया गया है। (वर्तमान उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं हैं, शब्दों को हटाकर) निम्नानुसारः

"(60) "राज्य सरकार",

(अ)

(ख)

(ग) संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ होने के बाद किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में, एक राज्य में, राज्यपाल और एक केन्द्र शासित प्रदेश में, केन्द्र सरकार का मतलब होगा।''

केंद्र शासित प्रदेश' शब्द को धारा 3 (62ए) में परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ है "संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश और इसमें भारत के क्षेत्र के भीतर कोई भी अन्य क्षेत्र शामिल होगा, लेकिन उस अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं होगा।"

संसद ने केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को अधिनियम, 1963 (संक्षेप में '1963 अधिनियम') में अधिनियमित किया। इसके लंबे शीर्षक से अधिनियम के अंतर्निहित

उद्देश्य काो प्रकट करता है, अर्थात कुछ केन्द्र राज्य प्रदेशों के लिए विधानसभाओं और मंत्रीपरिषद और कुछ अन्य मामलों के लिए प्रावधान करना। केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव 1963 के अधिनियम की धारा 2 (एच) द्वारा शासित है। 'प्रशासक' शब्द को धारा 2 (क) में परिभाषित किया गया है। 1963 के अधिनियम के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक' है। अनुच्देद 239 धारा 18 राज्य सूची या सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले को शामिल करने के लिए किसी केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभा की विधायी शक्ति का विस्तार निर्दिष्ट करता है। धारा 44 यह प्रावधान है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होंगे जो उन मामलों के संबंध में प्रशासक को अपने कार्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देंगे जिनके संबंध में केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति है, सिवाय इसके कि जहां तक वह अधिनियम द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से या किसी भी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने के लिए किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत कार्य करने के लिए अपेक्षित है। धारा 44 (1) में प्रावधान है जो प्रशासक की स्थिति और मंत्रिपरिषद की शक्तियों पर प्रकाश डालता है। परंतुक के अनुसार किसी भी मामले में प्रशासक और मंत्रियों के बीच मतभेद की स्थिति में, प्रशासक इसे राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्णय के लिए राष्ट्रपति को भेजेगा। इस प्रकार प्रशासक की कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति द्वारा विस्तारित किए गए सभी विषयों तक फैली हुई है। परंतुक के अनुसार किसी भी मामले में प्रशासक और मंत्रियों के बीच मदभेद की स्थिति में प्रशासक उसे राष्ट्रपति आदि द्वारा दिए गए निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगा। इस प्रकार प्रशासक की कार्यकारी शक्ति सभी विषयों तक विस्तारित होती है लेकिन मतभेद में राष्ट्रपति की भूमिका निर्णायक है। धारा 45 में प्रावधान है कि 'किसी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी । धारा 46

राष्ट्रपति को कार्य संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 55 में प्रावधान है किसीा केन्द्र शासित प्रदेश के संबंध में सभी अनुबंध संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किए गए अनुबंध है और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संबंध में सभी मुकदमे और कार्यवाही किसके द्वारा शुरू की जायेगी या सरकार के खिलाफ। अनुच्छेद 240 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अन्य बातों के साथ गोवा, दमन और दीव (कानून) विनियम, 1962 को अधिनियमित किया है। विनियमन के खंड (3), अधिनियम में संलग्न अनुसूची में सूचीबद्घ अधिनियमों को अनुसूची में निर्दिष्ट संशोधनों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए गोवा, दमन और दीव तक विस्तारित किया गया था। अनुसूची में बिना किसी संशोधन के समग्र रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 शामिल है

अधिनियम की धारा 10 (1) उपयुक्त सरकार किसी औद्योगिक विवाद को निर्णय के लिए धारा में उल्लिखित विभिन्न प्रकरणों में से किसी एक को भेजने की शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार संदर्भ देने की शक्ति उपयुक्त सरकार की शक्ति है। जिस उद्धरण को उच्च न्यायालय का समर्थन मिला वह यह है कि संघ द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए श्रमिकों द्वारा उठाए गए औद्योगिक विवाद के संबंध में, जिसे मोटे तौर पर लौह अयस्क के नमूने के रूप में वर्णित किया गया है, उपयुक्त सरकार राज्य सरकार है न कि केंद्र सरकार और जैसा कि इस मामले में संदर्भ केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र के बिना है, औद्योगिक न्यायाधिकरण ने उस पर निर्णय लेने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं किया है।

क्या किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को राज्य सरकार के रूप में वर्णित करना संवैधानिक रूप से सही होगा? अनुच्छेद 1 में प्रावधान है कि 'भारत, जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा'।उप-अनुच्छेद (2) में प्रावधान किया गया है कि 'राज्य और उनके क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए होंगे'। उप-अनुच्छेद (3) ने

संविधान में समझे गए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच एक द्वंद्व की शुरुआत की, जब यह प्रावधान किया गया कि भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे-(ए) राज्यों के क्षेत्र; और (बी) पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश। भाग प्रथम कर्मचारियों ए. एस. ओ. सी. एन. के प्रावधान। वी. जी. एस. को. (देसाई, जे.) संविधान का VI केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होता है। भाग संविधान का छठा भाग जो राज्यों से संबंधित है, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि केंद्र शासित प्रदेश एक राज्य नहीं है। इसलिए, केंद्र शासित प्रदेश संवैधानिक रूप से एक राज्य के अलावा कुछ और है। जहाँ तक राज्यों का संबंध है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए यद्यपि एक ही व्यक्ति को नियुक्त करने की अनुमति होगी दो या अधिक राज्यों के राज्यपाल के लिए भाग VIII केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासक का प्रावधान करती है। अनुच्छेद 239 राष्ट्रपति को केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासन की शक्ति प्रदान करता है। जब तक संसद के किसी अधिनियम द्वारा अन्यथा प्रदान न किया हो इसलिए अधिनियम 1897 में अधिनियमति "केन्द्र सरकार", "राज्य सरकार" और " केन्द्र शासित प्रदेश" अभिव्यक्तियों के अलावा, संविधान स्वयं राज्य और उसकी सरकार के बीच अंतर करता है। जिसे राज्य सरकार और संघ कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश को क्षेत्र और प्रशासन। जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से अधिनियमित नहीं किया जाता है, अभिव्यक्ति 'राज्य केंद्र शासित प्रदेश को नहीं समझेगा' और ' राज्य सरकार संघ के प्रशासन को नहीं समझेगी । अब अगर हम तीन अभिव्यक्ति की परिभाषा को याद करते हैं 'केंद्र सरकार' (धारा 3 (8), 'राज्य सरकार' (सामान्य में धारा 3 (60) और केंद्र शासित प्रदेश (धारा 3 (62 ए) खंड अधिनियम, यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगा कि संविधान निर्माताओं और संसद ने भी इन परिभाषाओं को अधिनियमित किया कि वे निर्माता इन परिभाषाओं को लागू करते समय राज्य सरकार अाैर केन्द्र शासक के प्रशासक के बीच संविधान द्वारा प्रदत्त अंतर स्पष्ट रूप से बरकरार रखा है। यह विशेष

रूप से अभिव्यक्त केन्द्र सरकार की परिभाषा में स्पष्ट किया गया है कि किसी केन्द्र शासक के प्रशासक के संबंध में किया गया है। किसी केंद्र शासित प्रदेश का राज्य, उसके भीतर कार्य करने के लिए अनुच्छेद 239 के तहत उसे दिए गए अधिकार के दायरे में कार्य करने वाली केन्द्र सरकार अभिव्यक्ति में समझा जायेगा। जब इस समावेशक भाग को इसके साथ रखा जाता है अभिव्यक्ति " राज्य सरकार" की परिभाषा में बहिष्कृत भाग के साथ स्थिति जो यह प्रावधान करती है कि संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956, के प्रारंभ के बाद किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में इसका मतलब, एक राज्य में, राज्यपाल होगा और एक केन्द्र शासित प्रदेश, केन्द्र सरकार में अभिव्यक्ति " राज्य सरकार" और " केन्द्र शासित प्रदेश" में प्रशासन के बीच वैचारिक रूप से अंतरस्पष्ट रूप से उभरता है। इसलिए, इस बात में कोई संदेह की गुंजाईश नहीं है कि अभिव्यक्ति ' एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन', प्रशासक का वर्णनन चाहे कितना भी किया गया हो किसी भी अधिनियम में प्रयुक्त अभिव्यक्ति " राज्य सरकार" में नहीं समझा जायेगा। इन परिभाषाओं को उनके वर्तमान स्वरूप में लाने के लिए संशोधन किया गया है। कानूनों का अनुकूलन (संख्या 1) आदेश 1956। सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाए गए सभी सामान्य अधिनियमों और विनियमों में जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो, तब तक उसमें परिभाषित शब्दों का वही अर्थ होगा जो उसमें निर्दिष्ट किया गया है। निर्विवाद रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 एक केंद्रीय अधिनियम है जो इसके प्रारंभ के बाद अधिनियमित किया गया है।सामान्य खंड अधिनियम और प्रासंगिक परिभाषाओं को संवैधानिक और वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुनर्गठित किया गया है, 'केंद्र सरकार,' राज्य सरकार 'और' केंद्र शासित प्रदेश 'अभिव्यक्तियों को सामान्य नियम में प्रत्येक को दिए गए अर्थ को प्राप्त करना चाहिए जब तक कि जिस विषय या संदर्भ

में इसका उपयोग किया जाता है, उसमें कुछ भी प्रतिकूलता हमारे संज्ञान में नहीं लाई गई। इसलिए इन अभिव्यक्तियों को उन्हें निर्दिष्ट अर्थ प्राप्त होना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने परिभाषाओं का उल्लेख करने के बाद उपरोक्त तीन अभिव्यक्तियाँ जैसा कि यहाँ निर्धारित और चर्चा की गई हैं पहले देखा गया कि परिभाषा को ध्यान से पढ़ने पर, ऐसा प्रतीत होता है ' कि किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संबंध में उसका प्रशासक इसके भीतर कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत उसके दिए गए अधिकार का दायरा केन्द्र सरकार है, अभी तक विवाद नहीं है। उच्च न्यायालय ने तब कहा कि उसे यह मानना होगा कि जहाँ तक केंद्र शासित प्रदेश का संबंध है, प्रशासक राज्य सरकार की परिभाषा में प्रदान किया गया है सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (60) में राज्य सरकार की परिभाषा में प्रदान किया गया। उच्च न्यायालय ने धारा 3 (60) के खंड (सी) की व्याख्या करने में त्रुटि में पड़ गया, जो इसके वास्तविक निर्माण पर दिखायेगा कि केन्द्र शासित प्रदेश में, राज्य सरकार अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है, केन्द्र शासित प्रदेश के संबंध में, केन्द्र सरकार राज्य सरकार होगी। इस परिभाषा से केन्द्र शासित प्रदेश के संबंध में राज्य सरकार की अवधारणा ही खत्म हो गई है। हालाँकि, हमारा ध्यान सत्य देवी बुशहरी बनाम पदम देव और अन्य में इस न्यायालय के दो निर्णयों और मध्य प्रदेश राज्य बनाम श्री मौला बक्स और अन्य में इस न्यायालय के निर्णय की और आकर्षित हुआ था, जिसमें भाग सी राज्यों के संदर्भ में, कुछ टिप्पणियां की गई है कि भाग सी राज्यों को प्रशासित करने के लिए अनुच्छेद 239 के तहत प्रदत्त अधिकार जैसा कि तब था, दिया गया। उन राज्यों को केंद्र सरकार में परिवर्तित करने का प्रभाव नहीं है, और यह कि अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति भाग सी राज्यों के संबंध में अधिकार रखते हैं, जो भाग ए में राज्यों का राज्यपाल और भाग बी राज्यों में राज्यों के एक राजप्रमुख के अनुरूप स्थिति रखता है। यह भी देखा गया कि 'यद्यपि भाग सी राज्यों को अनुच्छेद

239 के प्रावधानों के तहत केंद्रीकृत रूप से प्रशासित किया जाता है फिर भी वे राज्य नहीं रह जाते है और केंद्र सरकार में विलय नहीं हो जाते हैं।' तब यह आग्रह किया गया कि संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा अनुच्छेद 239 और 240 में संशोधन और संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 1962 द्वारा अनुच्छेद 239 ए और 239 बी को लागू करने से केवल भाग सी राज्यों के नामकरण में बदलाव आया है, जिसे अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वर्णित किया जा रहा है, केन्द्र शासित प्रदेश की स्थिति वही है जो भाग सी राज्यों के रूप में थी और इसलिए, उपरोक्त निर्णयों में लिया गया दृष्टिकोण कि भाग सी राज्यों के प्रशासन को उचित रूप से राज्य के रूप में वर्णित किया जा जाता है। जैसा कि राज्य सरकार यथाेचित परिवर्तनों के साथ केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन पर लागू करेगी। दूसरे शब्दों में, यह कहा गया था कि उन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए उचित रूप से राज्य सरकारों के रूप में वर्णित किया जा सकता है।दोनों निर्णय 1956 में संविधान के भाग VIII के संशोधन और 1962 में अनुच्छेद 239 ए और 239 बी को शामिल करने से पहले और विशेष रूप से 1963 के अधिनियम के अधिनियमन के बाद दिए गए थे। विधान सभा के साथ या उसके बिना और निर्दिष्ट विधायी और कार्यकारी शक्तियों के साथ मंत्रिपरिषद के साथ या उसके बिना केंद्र शासित प्रदेश की अवधारणा 1963 के अधिनियम में निर्धारित की गई है। इसके साथ, उपरोक्त तीन अभिव्यक्तियों की परिभाषाओं में संशोधन किए गए। इसलिए, दोनों निर्णय वर्तमान के समाधान में कोई सहायता नहीं करते है।

तब यह बताया गया कि अभिव्यक्ति की परिभाषा ' अधिनियम की धारा 2 (ए) (आई) में 'उचित सरकार' की परिभाषा जब तक कि इसे केन्द्र के अधिकार के तहत या उसके तहत किए गए किसी भी उद्योग से संबंधित किसी भी आैद्योगित विवाद के संबंध में नहीं दिखाया गया हो, सरकार या प्रगणित उद्योग या बैंकिंग या बीमा कंपनी, खान, एक तेल क्षेत्र, एक छावनी बोर्ड, या एक प्रमुख बंदरगाह, उपयुक्त केंद्र सरकार

होगी और किसी अन्य मामले में राज्य सरकार होगी। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया था कि जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि संघ द्वारा उठाए गए औद्योगिक विवाद के संबंध में संघ, उपयुक्त सरकार केंद्रीय होगी सरकार, मामला अवशिष्ट प्रावधान के तहत आएगा, अर्थात्, कि किसी अन्य औद्योगिक विवाद के संबंध में, राज्य सरकार ही मूल्यवान सरकार होगी। प्रस्तुतिकरण हमारे लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इससे पहले कि कोई यह कह सके कि औद्योगिक विवाद के संबंध में उपयुक्त सरकार राज्य सरकार है, कुछ राज्य सरकार होनी चाहिए जिससे शक्ति संदर्भ बनाने के लिए स्थिति होनी चाहिए लेकिन कोई अन्य सरकार है यदि कोई राज्य सरकार नहीं है, लेकिन कोई अन्य सरकार है जिसे केन्द्र शासित प्रदेश का प्रशासक कहा जाता है, तो सवाल उठेगा कि क्या ऐसी स्थिति में केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन को धारा 2 (ए) (आई) के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए। धारा 10 (1) के साथ पढ़े।

उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से एक त्रुटि में पड़ गया जब उसने कहा कि 'राज्य सरकार' अभिव्यक्ति की समावेशी परिभाषा आवश्यक रूप से अभिव्यक्ति का दायरा नहीं बढ़ाती है, लेकिन हो सकता है कभी-कभी विपरीत की ओर इशारा कर सकती है। बिना यह तय किए मान लीजिए कि ऐसा ही है। लेकिन जहाँ उच्च न्यायालय गलती में पड़ गया था जब यह अभिनिर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय सरकार और प्रशासक का प्रतिनिधित्व करते है और राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति प्रशासक की नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति के सभी आदेशों के अधीन एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए दो अलग-अलग सरकारे बनती है। राष्ट्रपति के संबंध में प्रशासक की स्थिति, शक्ति, कर्तव्यों और कार्यों की अनदेखी की गई है। संविधान और 1963 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि राज्य सरकार की अवधारणा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए विदेशी है और अनुच्छेद 239 में

प्रावधान है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाना है। राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य कर सकता है। इस प्रकार प्रशासक राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। उनकी स्थिति किसी राज्य के राज्यपाल की स्थिति से बिल्कुल अलग होती है। प्रशासक अपने मंत्री के साथ मतभेद कर सकता है और फिर उसे राष्ट्रपति के आदेश प्राप्त करने होंगे, जिसका अर्थ है केंद्र सरकार का आदेश प्राप्त करना होगा। इसलिए, किसी भी कीमत पर केन्द्र शासित प्रदेश का प्रशासक राज्य सरकार के विवरण के लिए योग्य नहीं है। इसलिए, केंद्रीय सरकार 'उपयुक्त सरकार' है।

यदि उपयुक्त सरकार के रूप में केन्द्र सरकार ने संदर्भ दिया है, तो संदर्भ को रद्द करने में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से गलती की थी।

अपीलकर्ता- संघ के विद्वान वकील ने एक वैकल्पिक दलील दी कि विवाद में शामिल कामगार एक प्रमुख बंदरगाह में काम करने वाले कामगार है और गोदी कर्मचारी हैं और वहाँ सबसे पहले, केन्द्र सरकार धारा 10 (1) के तहत संदर्भ देने के उद्देश्य से उपयुक्त सरकार होगी। इस विवाद को प्राधिकरण का समर्थन मिला। उच्च न्यायालय यह कहते हुए विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचा कि लौह अयस्क के नमूने लेने वाले किसी बंदरगाह से जुड़े किसी भी कार्य में शामिल नहीं है और न ही वे गौदी कर्मचारी है। हम इस वैकल्पिक प्रस्तुतिकरण की जाँच करने का प्रस्ताव नहीं करते है क्योंकि यदि संदर्भ को सक्षम माना जाता है, तो संदर्भ को बनाए रखने के लिए दूसरे तर्क की विस्तृत जाँच करना आवश्यक नहीं है। हालाँकि, यह आग्रह किया गया कि गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए संदर्भित औद्योगिक विवाद की जाँच करते समय न्यायाधिकरण के समक्ष इस पहलू पर फिर से विचार किए जाने की संभावना है। इस स्थिति में उचित बात यह है कि पक्षों के बीच विवाद को खुला रखा जाए। न्यायाधिकरण इस समझौते की जांच करने के लिए स्वतंत्र होगा। कि क्या लौह अयस्क

के नमूने लेने वाले किसी प्रमुख बंदरगाह से जुड़े या उससे संबंधित किसी काम में शामिल हैं या वे गोदी कर्मचारी हैं। न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अप्रभावित अपने स्वयं के निर्णय पर आ सकता है और यदि प्रश्न की जाँच की आवश्यकता है इसकी फिर से जांच करनी होगी।

तदनुसार, इन सभी पाँच अपीलों की अनुमति है और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है और न्यायाधिकरण ने प्रारंभिक बिंदु पर विशेष रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (1) के तहत संदर्भ देने के लिए केंद्र सरकार के संयोजन के बारे में, यहां उल्लिखित कारणों की पुष्टि की है। उत्तरदाताओं को प्रत्येक मामले में अपीलकर्ता को रूपये की लागत का भुगतान करना होगा। कुल 1,000/- रूपये प्रतिवादियों द्वारा अपीलकर्ता को लागत के रूप में 5,000/- रूपये का भुगतान किया जायेगा।

चूंकि विवाद पुराना है, वर्षों से समाधान लटकाया हुआ है। समाधान, न्यायाधिकरण को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने और आज से छह महीने की अवधि के भीतर गुण-दोष के आधार पर इसका निपटारा करने का निर्देश दिया गया है।

एनवीके. अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सिध्दार्थ संदू (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।